

 *Mahendra's*

TOPIC WISE GS / GK



**Directive Principles
Of State Policy
Concept With MCQs**



ALL COMPETITIVE EXAMS

LIVE   **3:00 PM**

NEVER
GIVE UP
BECAUSE
GREAT THINGS

Take time

**For Your Any Type of GA/GS Related Queries
Join Telegram Channel :**

**<https://t.me/jitendraMahendras>
jitendra Mahendras GS**

**Get Additional 10% Discount On All Products & Services of
Mahendras**

Use code : E009159

- These provisions, contained in Part IV (Article 36–51) of the Constitution of India, are not enforceable by any court.
- The framers of the Constitution borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution.
- Dr. B.R. Ambedkar describes these principles as “noble features” of the Indian Constitution.
- The directive principles along with the Fundamental Rights contain the philosophy of the Constitution and is the soul of the Constitution.
- Granville Austin has described the Directive Principles and Fundamental Rights as the “Conscience of the constitution”.
- भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित ये प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं।
- संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की "महान विशेषताओं" के रूप में वर्णित किया है।
- मौलिक अधिकारों के साथ निर्देशात्मक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन शामिल है और यह संविधान की आत्मा है।
- ग्रानविले ऑस्टिन ने निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को "संविधान का विवेक" के रूप में वर्णित किया है।

- Features of Directive Principles:
- The State should keep in mind while formulating policies and enacting laws.
- These are the Constitutional instructions or recommendations to the State in legislative, executive and administrative matters.
- The Directive Principles constitute a very comprehensive economic, social and political programme for a modern democratic State. They aim at realizing the high ideals of Justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble to the Constitution.
- **निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं:**
- राज्य को नीति बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए।
- ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं।
- एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का निर्देश सिद्धांत है। वे संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों को साकार करना चाहते हैं।



Features of Directive Principles:

- The Directive Principles are non Justiciable in nature, that is they are not legally enforceable by the court for their violation.
- The Directive Principles, though non-justiciable in nature, help in examining and determining the constitutional validity of law.
- They embody the concept of a welfare state and not that of a police state.
- To establish economic and social democracy in the country.
- **निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं:**
- निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर न्यायसंगत हैं, कि वे अपने उल्लंघन के लिए अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।
- निर्देशक सिद्धांत, हालांकि प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं, कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने और निर्धारित करने में मदद करते हैं।
- ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाते हैं, न कि किसी पुलिस राज्य की।
- देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना ।

- They can be classified into three broad categories, such as socialist, Gandhian and liberal-intellectual.
 - **Socialist principles:**
 - Article 39 - Certain principles of policy to be the State
 - Article 39 A - Equal justice and free legal aid
 - Article 41 - Right to work, to education and to public assistance in certain cases
 - Article 42 - Provisions for just and human conditions of work and maternity relief
-
- उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि समाजवादी, गाँधीयन और उदार-बौद्धिक।
 - **समाजवादी सिद्धांत:**
 - अनुच्छेद 39 - राज्य होने के लिए नीति के कुछ सिद्धांत
 - अनुच्छेद 39 ए - समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता
 - अनुच्छेद 41 - कुछ मामलों में शिक्षा, और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार
 - अनुच्छेद 42 - काम और मातृत्व राहत की सिर्फ और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान



- Article 47 - The Constitution of India is one of the Directive Principles which directs the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.

- अनुच्छेद 47 - पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य

➤ **Gandhian Principles:**

- Article 40 - Organization of village panchayats

- Article 43 - Living wage for workers

- Article 43 A - Participation of workers in management of industries

- Article 46 - Promotion of educational and economic interests of Schedules Castes, Schedules Tribes and other weaker sections

➤ **गांधीवादी सिद्धांत:**

- अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन

- अनुच्छेद 43 - श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी

- अनुच्छेद 43 ए - उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

- अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

➤ **Liberal-Intellectual principles:**

- **Article 44** - Uniform civil code for the citizens
- **Article 45** - **Provision for early childhood care and education to children below the age of six years**
- **Article 48** - Organization of agriculture and animal husbandry
- **Article 48 A** - Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life
- **Article 49** - Protection of monuments and places and objects of national importance
- **Article 50** - Separation of judiciary from executive
- **Article 51** - Promotion of international peace and security

➤ **उदार-बौद्धिक सिद्धांत:**

- अनुच्छेद 44 - नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
- अनुच्छेद 45 - छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान
- अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन का संगठन
- अनुच्छेद 48 ए - पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा
- अनुच्छेद 49 - राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद 50 - न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
- अनुच्छेद 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

Fundamental Duties

- It shall be the duty of every citizens of India:
- d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 1976 में संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा अपनाया गया।
- संविधान के भाग IV-A में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 29 (1) और जापान, चीन, यूएसएसआर आदि जैसे देशों के संविधान अनुरूप लाने की आवश्यकता है।

























































